

प्रेषक,

श्रीमती इन्दिरा आशीष,
सचिव, न्याय एवं विधि परामर्शो,
उत्तरांचल शासन ।

सेवा में,

महानिबन्धक,
मा० उत्तरांचल उच्च न्यायालय,
नैनीताल ।

न्याय अनुभाग : 2

देहरादून : दिनांक : १७ अक्टूबर, 2006

विषय: जिला न्यायालय भवन, नैनीताल के विश्राम कक्ष, कार्यालय कक्ष एवं चतुर्थ श्रेणी के आवासों को रंगाई-पुताई हेतु वित्तीय वर्ष 2006-07 में धनराशि की स्वीकृति ।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या-3613/2005/UHC/Admin.B/Const, दिनांक 18.11.2005 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निर्देश हुआ है कि जिला न्यायालय भवन, नैनीताल के विश्राम कक्ष, कार्यालय कक्ष एवं चतुर्थ श्रेणी के आवासों को रंगाई-पुताई हेतु वित्तीय वर्ष 2006-07 में अनुरक्षण मद से ₹० 2,60,000/-की लागत के आगणन का टी०ए०सी० से परीक्षणोपरान्त प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान करते हुए रुपये 2,60,000/- (रुपये दो लाख साठ हजार मात्र) की धनराशि के व्यय किये जाने की भी स्वीकृति महामहिम राज्यपाल निम्न शर्तों के अधीन सहर्ष प्रदान करते हैं :-

- (1) आगणन में उल्लिखित दरों का विश्लेषण विभाग के अधीक्षण अभियन्ता द्वारा स्वीकृत/अनुमोदित दरों को, जो दरें शिड्यूल ऑफ रेंट में स्वीकृत नहीं हैं, अथवा बाजार भाव से ली गई हो, की स्वीकृति नियमानुसार अधीक्षण अभियन्ता का अनुमोदन आवश्यक होगा ।
- (2) कार्य कराने से पूर्व समस्त कार्यों के विस्तृत आगणन गठित कर नियमानुसार सक्षम प्राधिकारों से प्राविधिक स्वीकृति प्राप्त की जाय, तदोपरान्त ही कार्य प्रारम्भ किया जाय ।
- (3) कार्य को स्वीकृत लागत में ही पूर्ण कराना सुनिश्चित किया जाय । स्वीकृत नामों से अधिक व्यय करापि न किया जाय ।
- (4) निर्माण कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व समस्त औपचारिकताएं तकनीकी दृष्टि को मद्देनजर रखते हुए एवं लोक निर्माण विभाग द्वारा प्रचलित दरों/विशिष्टियों के अनुरूप ही कार्यों को सम्पादित किया जाय ।
- (5) कार्य कराने से पूर्व स्थल का भस्ती-भांति निरीक्षण उच्च अधिकारियों के साथ अवश्य कर ली जाय । निरीक्षण के पश्चात् आवश्यकतानुसार निर्देशों तथा निरीक्षण टिप्पणी के अनुरूप कार्य किया जाय ।
- (6) आगणन में धनराशि जिन मदों हेतु स्वीकृत की गई है, उसी मद में व्यय की जाय । एक मद की राशि दूसरी मद में किसी भी दशा में व्यय न की जाय ।
- (7) कार्य कराने समय यह सुनिश्चित करते कि वार्षिक अनुरक्षण से सम्बन्धित नियमों एवं नार्मस से अधिक किसी भी स्थिति में व्यय न की जाय । इसका पूर्ण दायित्व कार्यकारी इकाई का होगा ।
- (8) व्यय से पूर्व बजट मैनुअल, वित्तीय हस्त पुस्तिका, स्टोर पर्चेज रूलस, मितव्ययता के सम्बन्ध में समक-समय पर निर्गत आदेश एवं तद्विषयक अन्य आदेशों का अनुपालन किया जाय । कार्य की गुणवत्ता एवं समयबद्धता हेतु सम्बन्धित निर्माण एजेन्सी/अधिशक्तों अभियन्ता पूर्णरूप से उत्तरदायी होंगे ।

- (9) स्वीकृत की जा रही धनराशि का 31.3.2007 तक पूर्ण उपयोग कर स्वीकृत धनराशि की वित्तीय एवं भौतिक प्रगति का विवरण एवं उपयोगिता प्रमाण-पत्र शासन को उपलब्ध करा दिया जाय ।
- (10) निर्माण कार्य करत समय अथवा आगजन गठित करत समय मुख्य सचिव, उत्तरांचल के शासनादेश संख्या 2047/XVI/219(2006), 30.5.2006 द्वारा निर्गत आदेशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाय ।
- 2- इस सम्बन्ध में होने वाला व्यय वर्तमान वित्तीय वर्ष 2006-2007 की आय-व्यय की अनुदान संख्या-04 के अन्तर्गत लेखा-शीर्षक "2014 न्याय प्रशासन-00-आयोजनेतर-105-सिविल और सेशन न्यायालय-03-जिला तथा सेशन न्यायाधीश-00-29-अनुरक्षण" के नामे डाला जायेगा ।
- 3- यह आदेश वित्त अनुभाग-5 के अशासकीय संख्या-631/XXVII(5)/2006 दिनांक 17.10.2006 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे है ।

भवदीया,

(इन्दिरा आशीष)

सचिव ।

संख्या-50-चौ(1)/XXXVI(1)/2006-तद्दिनांक ।

- प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनाय एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-
1. महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी), ओबराय बिल्डिंग, उत्तरांचल, माजरा, देहरादून ।
 2. मुख्य सचिव, उत्तरांचल शासन, देहरादून ।
 3. वरिष्ठ कोषाधिकारी, नैनीताल ।
 4. मुख्य अभियन्ता, स्तर-1 लोक निर्माण विभाग, देहरादून ।
 5. अधिशासी अभियन्ता, निर्माण खण्ड, लोक निर्माण विभाग, नैनीताल ।
 6. नियोजन विभाग/वित्त अनुभाग-5, उत्तरांचल शासन ।
 7. एन०आई०सी०/सम्बन्धित समीक्षा अधिकारी/गार्ड फाईल ।

आज्ञा से,

(आलोक कुमार वर्मा)

अपर सचिव ।